

बदलती वैश्विक राजनीतिक और भारत-चीन संबंध

सारांश

बदलती वैश्विक राजनीति में विश्व के दो महान अभिकर्ता एवं उभरती हुई विश्व शक्तियों वैश्विक रूझानों को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है ये शक्तियाँ है भारत और चीन। भारत और चीन के ऐतिहासिक संस्कृति भले ही सहयोगात्मक रही है लेकिन वर्तमान परिदृश्य प्रतिद्वन्द्विता का है हालांकि भारत और चीन दोनों ने लगभग एक-साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। भारत ने जहाँ सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के मूल्यों को खुद में समाहित किया, वहीं चीन में आज भी लोकतंत्र तो है लेकिन बस नाम का। भारत चीन संबंधों की इस गाथा में अनेक स्याह मोड़ आए। 1962 के भारत-चीन युद्ध से लेकर हिन्दी चीनी भाई-भाई से होते हुए भारत-चीन संबंध आज इस दौर में हैं कि चीन खुलेआम समसामयिक मुद्दों खासकर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता, आतंकी मसूदा अजहर, पानी के मुद्दे एवं डोकलाम आदि के मुद्दों पर तनाव है वही बुहान जैसे वार्ता से संबंधों में प्रगाढ़ता आयी है। जो दोनों देश के हित में है।

मुख्य शब्द : वैश्विक राजनीति, प्रतिद्वन्द्विता, अर्थव्यवस्था, विस्तारवादी, संघर्ष, अनौपचारिक मुलाकात, तनाव, टकराव, संवेदनशीलता।

प्रस्तावना

दरअसल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और हिन्द-प्रशांत महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों में राजनयिक गतिविधियाँ चरम पर है। पुराने समीकरण ध्वस्त हो रहे हैं, नए समीकरण उभर रहे हैं। इन्हीं के मध्य चीन इस असमंजस में है कि वह भारत के प्रति कौन-सा रास्ता अपनाए। दोनों देशों के मध्य विकसित व्यापार और विश्व परिदृश्य में उनकी सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था उनके बीच संघर्ष रोकने वाला कारक मानी जा रही है, किन्तु चीन के लगातार पाकिस्तान के आंतकियों के समर्थन, डोकलाम पर विस्तारवादी नीति, उसे हडपने की साजिश और हिन्द-प्रशांत सागर क्षेत्र में वियतनाम को लेकर उसका रूख भारतीय रक्षा-विशेषज्ञों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। प्रस्तुत आलेख 58वाँ ऑल इंडिया पॉलिटिकल साइंस कन्फ्रेंस एन्ड इंटरनेशनल कन्फ्रेंस ऑन स्पाइरिंग इंडिया 29-30 दिसम्बर 2018 प्रस्तुत पत्र का अद्यतन एवं परिष्कृत पत्र है।

इस आलेख के आरम्भ में ही इस बात को रेखांकित करना आवश्यक है कि भारत-चीन संबंधों में पानी मुख्य सुरक्षा मुद्दे के रूप में उभर रहा है। यह दोनों देशों के बीच आपसी विवाद का बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि गंगा को छोड़कर एशिया की तमाम बड़ी नदियों का उद्गम चीनी नियंत्रण वाला तिब्बत क्षेत्र है। जब से भारत और चीन आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, उसी समय से उन पर दुनिया भर की निगाहें लगी हैं। ये दो जनसांख्यिकीय दिग्गज आर्थिक विकास के सत्ता परिवर्तन को रेखांकित करने में मददगार बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों में सामरिक विक्षोभ और शत्रुता की ओर अधिक ध्यान नहीं जाता। बहुत तेजी से शक्तिशाली होता जा रहा चीन एशिया में प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठने के लिए संकल्पबद्ध नजर आता है।¹

हालांकि खतरनाक बात यह है कि आज चीन तिब्बत क्षेत्र से अन्य नदियों को जोड़ने की बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इससे इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का पानी भारत नहीं पहुँच पाएगा और भारत व अन्य संबद्ध देशों की अनेक नदियाँ सूख जायेंगी,² किन्तु इससे पहले कि पानी स्थानांतरित करने की ये परियोजनाएँ चालू हों, चीन को एक व्यवस्थागत नीति तैयार कर लेनी चाहिए और जिन देशों में चीन के उद्गम वाली नदियाँ बहती हैं, उनसे परस्पर सहयोग पर आधारित समझौता कर लेना चाहिए।

दरअसल चीन का सबसे खतरनाक विचार है ब्रह्मपुत्र को मोड़ना। तिब्बत में यारलंग तसांगपो और चीन में यलजैंगबू के नाम से जाने जानी वाली ब्रह्मपुत्र का रूख चीन उत्तर की तरफ मोड़ना चाहता है। यह संसार के सबसे



सत्येन्द्र कुमार

शोध-छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग, बी.
आ.ए.बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

ऊँचे स्थान से निकलने वाली नदी है। यह सबसे तेज प्रवाह वाली नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी का रुख मोड़कर इसे येलो नदी में डालने की योजना के बारे में चीन सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता क्योंकि इस परियोजना के शुरू होते ही निम्नवर्ती चीन का भारत और बांग्लादेश के साथ जल युद्ध छिड़ जायेगा। यह योजना भारत के पूर्वोत्तर के मैदानों और पूर्वी बांग्लादेश के पर्यावरण को पूरी तरह बिगाड़ सकती है।³

अध्ययन का उद्देश्य

इस आलेख का उद्देश्य विश्व राजनीति के शक्ति संतुलन परिवर्तन हो रहा है ऐसी स्थिति में भारत-चीन के संबंधों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। भारत-चीन के संबंधों में हो रहे इनकी स्वाभाविक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाना है।

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य

दुनिया में अपनी धौंस को निरंतर बढ़ाने में लगा हुआ चीन समय-समय पर भारत के साथ लगती हुई अपनी सीमा को विवादित बताकर जिस तरह से घुसपैठ करता ही रहता है वह आनेवाले समय में भारत और चीन दोनों के लिए किसी बड़े संकट का कारण भी बन सकता है। चीन के साथ लगती हुई लम्बी और दुर्गम पहाड़ी सीमा के कारण वहाँ पर भारत द्वारा भी वैसे उपाय नहीं किए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता है क्योंकि कुछ इलाकों में भारत की तरफ से सीमा पर पहुँचना कड़ी चुनौती है जबकि चीन की तरफ से वहाँ तक पहुँचना उतना कठिन नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में इसी तरह से कहीं पर भारत मजबूत सामरिक स्थिति में है तो कहीं पर चीन पर भारत ने आज तक कभी भी चीन की सीमा का कहीं भी अतिक्रमण नहीं किया है। हाल के वर्षों में जिस तरह से लद्दाख क्षेत्र में चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में आकर अपने तम्बू लगाये और उनकी सूचना मिलने पर फिर से उसी तरह की बातों की गई जो हमेशा से ही की जाती रही हैं तो उससे चीनी और भारतीय रुख का भी पता चलता है?

लगातार परिवर्तित होती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण चीन अपनी सभी तरफ की सीमाओं में विस्तार करने की नीति पर काम कर रहा है और उसका यह भी मानना है कि जिन स्थानों पर वह सामरिक दृष्टि से कमजोर है और अपने इस तरह के प्रयासों से वह कुछ हासिल कर सकता है वह वहाँ पर ऐसी हरकतें करने में लगा हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण ही वह जापान से लगाकर अपने सभी पड़ोसियों से किसी न किसी छोटे-मोटे विवाद में लगा हुआ है जिसका लाभ उसे कई स्थानों पर मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आने वाले समय में वह अरब सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए पाक के साथ ग्वादर बंदरगाह के लिए अपना काम शुरू ही कर चुका है और पूरे एशिया क्षेत्र में अपनी सामरिक आवश्यकताओं को आज अपनी बढ़ती आर्थिक शक्ति के भरोसे बढ़ाने में लगा हुआ है।⁴ ऐसा नहीं है कि इससे पहले चीन का रुख भारत और अन्य पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा रहा है पर अब एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में वह ऐसी घटनाओं में कुछ अधिक ही दिलचस्पी दिखाने लगा है।

भारत के साथ उसकी सीमा से चीन को फिलहाल कुछ खास हासिल नहीं होने वाला तो नहीं है पर लम्बे समय में इस हिमालयी क्षेत्र में खनिज और प्राकृतिक संपदा के मिलने और उसके दोहन के समय चीन चुप भी नहीं बैठने वाला है शायद वह इसी सबको अपने हित में मानकर लगातार भारतीय सीमा का अतिक्रमण जानबूझकर करता ही रहता है जिससे आने वाले समय में इस बात को साबित कर सके कि यह क्षेत्र लम्बे समय से ही विवादित रहा है।⁵ अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण जिस तरह से चीन भारत के क्षेत्रों में आता है और बातचीत होने पर अधिकांश जगहों पर वापस पुरानी जगह पर वापस भी लौट जाता है। इस पूरे प्रकरण में उसकी नीतियों को एक बार फिर से समझने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक भारत के पास भी इस सबसे निपटने के लिए कोई कारगर नीति नहीं होगी, हम केवल इस तरह की घटना पर अपने विरोध के बाद चीन को उसकी पुरानी स्थिति में वापस भेजने में सफल होकर खुश होते रहेंगे।⁶

नरम-गरम नीति

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध या फिर संघर्ष आखिरी विकल्प होता है। शी इसे बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि उनके विदेश मंत्री वांग यी ने 2013 में एक कार्यक्रम में वक्तव्य दिया कि "चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी परस्पर शत्रु नहीं हैं बल्कि प्रगति की राह में परस्पर एक-दूसरे का हाथ थामे नृत्य करते हुए नई ऊँचाइयों को छू सकते हैं।"⁷

लेकिन यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर मंच पर अमेरिका द्वारा भारत को तरजीह दिये जाने से चीन की परेशानी में खासी वृद्धि हुई है। भारत के कई हिन्दी-चीन राष्ट्रों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध है। चीन की भारत विरोधी नीति भारत के लिए इन राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का कारक बन सकती है। इस संदर्भ में भारत-वियतनाम संबंध की मिसाल दी जा सकती है। वियतनाम को भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की खबरों पर चीन की चिंताओं को रेखांकित करते हुए ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में कहा गया है, "यदि भारत सरकार रणनीतिक समझौते या बीजिंग के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से वियतनाम के साथ असल में अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करती है तो इससे क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा होगी और चीन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा।"⁸ ग्लोबल टाइम्स ने यह बात इन खबरों का हवाला देते हुए कही कि नई दिल्ली का यह कदम चीन द्वारा भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य बनने से रोकने तथा जैश मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित कराने में चीन द्वारा अड़ंगा लगाये जाने के जवाब में है।⁹

अमेरिका की चुनौती: चीन में घेरने की योजना

हाल के दिनों में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की बहुपक्षीय बैठक के तत्काल बाद फ्रांस ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के संकेत दिये हैं। मनीला में हुए आसियान सम्मेलन के अलावा भारतीय अधिकारियों की

अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ चार-पक्षीय बैठक हुई थी। इस बैठक को क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फ्रांसीसी राजदूत अलेक्जेंडर जिग्लर की टिप्पणी को इसी के तहत देखा जा रहा है। उधर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन भारत यात्रा पर आये थे। इस यात्रा में भारत फ्रांस के साथ रिश्तों को और मधुर बनाने की बात हुई।

भारत फिलहाल मुंबई के मझगाव डॉकयार्ड लिमिटेड में छह स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। ये 2005 में फ्रांस के साथ किये गये 23,562 करोड़ रुपये के एक सौदे के तहत बनाई जा रही हैं। वहीं, 2015 में 7.7 अरब यूरो (59,000 करोड़ रुपये) के जिन 36 राफेल जेट विमानों की खरीद का समझौता हुआ था, उनकी पहली खेप फ्रांस 2019 तक भारत को देगा। इन सौदों से भारत-फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी मजबूत होगी।¹⁰ भारत के पड़ोसी मालदीव में आये संकट के बाद चीन की नौसेना की उपस्थिति को निष्क्रिय करने के लिए इस तरह की पहल आवश्यक है।

भारत-वियतनाम नजदीकी और चीन

हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच हुए परमाणु सहयोग समझौता बहुत अहमियत रखता है। वहीं संयुक्त बयान में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर देने की बात कह कर दोनों देशों ने चीन को कुछ संदेश देने का भी प्रयास किया है। भारत वियतनाम से राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और ऊर्जा से जुड़े पहलुओं पर समझौते किये हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सिद्धांतों को भी रेखांकित किया है। वियतनाम के पास दक्षिण चीन सागर में हालात गंभीर हैं, लेकिन फिलहाल उथल-पुथल कम दिख रही है। यहाँ चीन ने कृत्रिम द्वीप भी बनाया है, जिसे लेकर वियतनाम आपत्ति उठाता रहा है। ऐसे में यह एक संकेत है कि भारत और वियतनाम अपने-अपने दायरे में रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को अहमियत देते हैं।

वुहान से आगे का रास्ता

मोदी और जिनपिंग की चीन के शहर वुहान में अप्रैल 27-28, 2018 को हुई अनौपचारिक बैठक के दौरान जिनपिंग की मेजबानी, दोनों नेताओं की लंबी-लंबी मुलाकातों और एक-दूसरे के साथ मित्रवत रवैये पर दुनिया की खूब नजर रही। वैसे इस अनौपचारिक मुलाकात के कुछ ठोस निष्कर्ष भी सामने आए हैं और जिनसे भारत और चीन के बीच तनाव काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।¹¹ दोनों देश अफगानिस्तान में एक संयुक्त आर्थिक परियोजना चलाने पर सहमत हुए हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में भारत की किसी तरह की भी भूमिका से दिक्कत रही है, ऐसे में अगर भारत-चीन की यह परियोजना सफल हो जाती है तो इससे नई दिल्ली और बीजिंग के बीच अविश्वास कम करने में भारी मदद मिलेगी।

मोदी और जिनपिंग ने अपने-अपने देश की सेनाओं को 'रणनीतिक दिशा-निर्देश' भी जारी किये हैं ताकि सीमा पर दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थितियों से बचा जा सके।¹² इसका मतलब है कि भविष्य में भारत

और चीन के बीच डोकलाम विवाद जैसी घटनाओं की आशंका काफी कम हो जायेगी। इस लिहाज से यह कदम काफी अहम और स्वागत योग्य है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी-जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों से कहा गया होगा कि वे सीमा विवाद के निपटारे में तेजी लाएँ। हालांकि इसको लेकर सालों से कोशिशें चल रही हैं जबकि नतीजा अब तक सिफर ही है। अगर ये दोनों नेता भारत-चीन संबंधों के भविष्य को लेकर सच में कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले सीमा-विवाद को हल करना होगा। आखिर यही वो बुनियादी मुद्दा है जिसकी वजह से दोनों देशों की सेनाएँ जब-तब टकराव की स्थिति में आती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ 1962 में अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद चीन ने उसे खाली कर दिया था और इससे भी साबित होता है कि अब चीन द्वारा उस पर कोई दावा बेमतलब ही है।

चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर विवाद, आपसी व्यापार घाटा और 2017 में डोकलाम की तनातनी के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति थी जिनसींग के बीच वुहान में सम्पन्न अनौपचारिक बैठक का खास महत्व है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बीते कुछ महीनों से दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि आखिर भारत-चीन के संबंधों में परेशानी क्या है? और क्यों इन दोनों देशों के बीच इस तरह का सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ जिसके लिए विस्तृत बातचीत जरूरी हो गई? इसके कम से कम पाँच कारण हैं।¹³

पहला तो यह है कि नेहरू के जमाने से ही "हिंदी चीनी भाई-भाई" के नारे और 1962 के युद्ध से लेकर 2017 के डोकलाम विवाद तक भारत और चीन के रिश्ते शायद ही कभी सच्चाई की बुनियाद पर रहे। दो पड़ोसियों के रिश्तों में कभी बहुत उत्साह दिखता है, तो कभी इस बात से साफ इनकार कि सब कुछ ठीक है (या हो जाएगा), या फिर कभी आपसी बातचीत की कमी से पैदा हुई बेपरवाही, कड़वाहट और अविश्वास। इससे भी बुरी बात यह है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच चुनिंदा बातचीत होती है जिनसे सरकार के अलग-अलग विभागों, आम लोगों और मीडिया में आशंकाएँ पैदा हो जाती हैं।

दूसरे, भारत और चीन दोनों एक दूसरे के प्रभाव और विकास को बढ़ने से रोकने की खूब कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का चीन कथित रूप से प्रमुख विरोधी है, वह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी भारत के प्रवेश का विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामलों में भी जहाँ भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी आवाज रखता है, चीन ने उसका साथ नहीं दिया।

इसी तरह से अगर चीनी पक्ष की ओर से देखें तो उसे लगता है कि भारत के साथ समझौता करना मुश्किल काम है। भारत उन चुनिंदा देशों में है, जो चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन नहीं कर रहे

हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह परियोजना बेहद खास है। चीन क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डॉयलॉग में भारत के शामिल होने की वजह से भी आशंकित है। इसमें अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया भी हैं। चीन मानता है कि यह ग्लोबल पावर के रूप में उसके उभार को कम करने का एक औजार है।

तीसरा, चीन शीतयुद्ध के बाद की राजनीति का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला देश है। उसे अंतर्राष्ट्रीय उदारवाद का भी खूब फायदा मिला है। चीन ने जापान के ओवरसीज डेवलपमेंट अस्सिस्टेंट (ओडीए) का बड़ा लाभ लिया है। हालांकि अब भारत जापान के ओडीए का ज्यादा लाभ ले रहा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका का समर्थन पा रहा है। चीन इसे भविष्य की सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में देखता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेंटागन में बैठे "अधिकारी" चीन के असर को संतुलित करने के लिए भारत का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे।

चौथा, चीन अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी जगत पर कूटनीति में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाता है, लेकिन खुद चीन भी इस बीमारी से मुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका के साथ एक नई तरह के शक्ति संबंधों की वकालत करते हैं। हालांकि खुद चीन एशिया के ताकतवर देशों भारत और जापान की अनदेखी करता है, जबकि ये दोनों देश से भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों के मामलों में जहाँ भारत के सीधे हित जुड़े हुए हैं, वहाँ भी चीन भारत से मशविरा लेने का कोई तंत्र बनाने के खिलाफ है।

चीन इस बात की वकालत करता है कि किसी विवादित इलाके में तीसरे देश को निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन यह उपदेश वह खुद पर लागू नहीं करता। भारत के अरुणाचल प्रदेश में जापान के निवेश का विरोध, दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में चीन का निवेश इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। चीन का कहना है कि भारत उसकी पहल पर प्रतिक्रिया नहीं देता जिसके जवाब में भारत की दलील है कि वन बेल्ट वन रोड और चीन नेपाल भारत कॉरिडोर जैसी ज्यादातर परियोजनाओं के पहले मशविरा या पारदर्शी बातचीत नहीं की गई।

पाँचवां, सीमा विवाद, तिब्बती शरणार्थी, ब्रह्मपुत्र के पानी के बँटवारे जैसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में ऐसे बहुत से अनसुलझे मुद्दे हैं। चीन का रवैया कई दशकों से इन मुद्दों को सुलझाने वाला नहीं रहा है। चीन ने म्यांमार, रूस और यहाँ तक कि वियतनाम जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ अपने सीमा विवाद सुलझा लिए हैं लेकिन भारत के मामले में लगता है कि समाधान ढूँढ़ने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। एशिया के इन दो ताकतवर देशों के रिश्ते में भरोसे की कमी और सुरक्षा को लेकर असमंजस नजर आता है जिसे हटा कर निरंतर बातचीत, नियमित लेन-देन और एक-दूसरे के हितों और चिंताओं का मूल्यांकन करने की जरूरत है।

निष्कर्ष

मई 2014 के भारत में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही भारत ने चीन की तरफ गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। इसके बाद भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। इसके लिए नई दिल्ली ने समान सोच वाले देशों जैसे अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और वियतनाम से संबंधों को प्रगाढ़ किया है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादर बन्दरगाह का विकास कर रहा है और दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, वहीं भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की तरफ कदम बढ़ाकर चीन के इस कदम का मुँहतोड़ जवाब दिया है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता में आने से दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में दिलचस्पी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों के मद्देनजर रूस ने चीन की तरफ हाथ बढ़ाया था जिसका प्रभाव हमें चीन-रूस-पाकिस्तान के गठजोड़ के तौर पर देखने को मिला। अब हम ट्रम्प रूस के तो नजदीक जाना चाह रहे हैं लेकिन चीन से दूर भाग रहे हैं तो शायद यह समीकरण भारत के लिये हितकारी हो बशर्ते भारत फूँक-फूँक कर कदम बढ़ाए।

अंत टिप्पणी

1. इरा पाण्डे, *इंडिया चाईना : नेबर्स स्ट्रेन्जर, हार्पर कालिन्स, न्यू दिल्ली, 2010, पृ. 68-73*
2. प्रेम शंकर झा, *इंडिया एण्ड चाईना : द बैटल बिटवीन सॉफ्ट हार्ड पॉवर, पेनग्यून, न्यू दिल्ली, 2010, पृ. 29*
3. कैथलिन न्यूमैन, *चाईना एण्ड इंडिया : ए कम्प्लेक्स एण्ड ग्रोइंग रिलेशनशिप, नोवा पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली, 2015, पृ. 89-91*
4. हर्ष वी.पंत, *द चाईना सिन्ड्रोम : ग्रैपलिंग विद ऐन अनइजी रिलेशनशिप, हार्पर कॉलिन्स, न्यू दिल्ली, 2010, पृ. 37-41*
5. फ्रांसिस आर.फ्रैंकल, *इंडिया-चाईना रिलेशनशिप : राइवलरी एण्ड इंगेजमेंट, ऑक्सफोर्ड, न्यू दिल्ली, 2004, पृ. 12*
6. उपरोक्त
7. *द इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2013*
8. *ग्लोबल टाइम्स, 21 अगस्त, 2018*
9. उपरोक्त
10. अभिषेक प्रताप सिंह, *"रिसेटिंग इंडिया-चाईना टाइज", द पायोनियर, 30 अप्रैल, 2018*
11. हैपीमॉन जैकब, *"सब्सटान्स एण्ड ऑपटिक्स ऑफ द सम्मिट" द हिन्दू, 30 अप्रैल, 2018*
12. श्याम शरण *"द वुहान विंडो", द इंडियन एक्सप्रेस, 03 मई 2018*
13. कैथलिन न्यूमैन, *पूर्वोक्त, पृ. 93*